उप-चुनाव

+

*८५. श्री सुबोध हंसदा:
श्री प्रकाशवीर शास्त्री:
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती:
श्री स० चं० सामन्त:
श्री ब० कु० दास:
श्री म० ला० द्विवेदी:
श्री विभूति मिश्र:
श्री राम रतन गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया:
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बृजराज सिंह:
श्री ग्र० व० राघवन:
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री हेडा:
श्री भागवत झा आज़ाद:
श्री भक्त दर्शन:

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में होने वाले उप-चुनाव सम्बन्धी प्रस्तावों पर कोई विचार किया गया है ;

(ख) इन उप-चुनावों को कब तक रोके रखने का विचार है ; और

(ग) क्या कुछ ऐसे ज्ञापन मिले हैं जिनमें शीघ्र ही इन चुनावों को कराने का अनुरोध किया गया हो ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभूतेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). निर्वाचन आयोग ने सम्यक विचार करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया है कि जो उप-चुनाव विचाराधीन हैं, उन्हें अविलम्ब कराया जाए ।

(ग) निर्वाचन आयोग को ऐसा कोई भी ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें चुनाव शीघ्र कराने का अनुरोध किया गया हो ।

[(a) and (b). **After due consideration**, the Election Commission has decided to hold the pending bye-elections without any further delay.

(c) The Election Commission has not received any memorandum urging for early elections.]

Shri Subodh Hansda: May I know whether the Election Commission has issued any orders for holding any bye-elections by this time?

Shri Bibudhendra Misra: The Election Commission has already issued a press note, and the press note says that the notification calling the constituencies to elect will be issued some time in March, and the elections will be held either in the second week of April or in the third week of April.

Shri Bade *rose—*

Mr. Speaker: Now, the bye-elections are going to be held. Next question.

Shri Bade: I just want to know one thing.

Mr. Speaker: I am sorry. I have already passed on to the next question.

Shri Bade: There is a long list of names of Members who have tabled this question.

Mr. Speaker: Exactly that was the reason why I had passed on to the next question.

Shri Bade: I rose twice.

Mr. Speaker: I had seen him. Now, next question.

अखबारी कागज़

+

*८६. श्री भक्त दर्शन:
श्री भागवत झा आज़ाद
श्री बड़े :
श्री डी० चं० शर्मा:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखबारी कागज़ की उपलब्धि की क्या स्थिति है ; और

(ख) कुछ समय पहले अखबारों को अखबारी कागज देने पर जो नियंत्रण लगाये गये थे, उन की इस समय क्या स्थिति है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

[(a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.].

विवरण

(क) देश में अखबारी कागज बनाने का इस समय केवल एक कारखाना है जो मध्य प्रदेश में है और जिसका नाम नपा मिल्स है । इस कारखाने की संस्थापित क्षमता ३०,००० टन प्रति वर्ष है । इसका वार्षिक उत्पादन २५,००० से १६,००० टन तक है ।

(ख) चालू आयात नीति के अन्तर्गत अखबारों को अप्रैल, १९६१– मार्च, १९६२ में जितने अखबारी कागज की आवश्यकता हुई थी उसमें २१.२ प्रतिशत कटौती करके कोटा दिया जाता है । १०० टन से अधिक अखबारी कागज पाने के हकदारों के मामले में ७५ प्रतिशत तक कोटा आयात करने की अन्तिम रूप से अनुमति दी जाती है तथा शेष की पूर्ति नेपा के कागज से की जाती है । १०० टन से कम अखबारी कागज के हकदारों के कोटे में कोई कटौती नहीं की जाती और उन्हें सारा कागज आयात करने की अनुमति है । विदेशी मुद्रा की कमी के कारण बिक्री बढ़ जाने के लिये कोई अतिरिक्त कोटा नहीं दिया जाता । बिक्री बढ़ावे की दृष्टि से अखबारों को इस बात की स्वतन्त्रता होती है कि वे जैसे भी चाहें अपने ढंग की व्यवस्था कर सकते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का जो "क" खंड है उस का वास्तविक उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता था कि विदेशों से मंगा कर और अपने देश के उत्पादन को मिला कर न्यूजप्रिंट की इस देश के अन्दर क्या स्थिति है ?

श्री मनुभाई शाह : १,१२,००० टन की सालाना लागत है, जिस में से २३,००० टन हिन्दुस्तान में बनता है और ९८,००० टन बाहर से आता है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि जो बड़े-बड़े समाचार पत्र हैं, वे तो किसी प्रकार से अखबारी कागज प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन छोटे समाचार पत्रों के लिये एक बहुत बड़ी समस्या है, उन के लिए यह एक जीवन-मरण का प्रश्न हो जाता है ? इसलिये क्या उन के लिये कोई विशेष सुविधायें देने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : जो छोटे समाचार पत्र होते हैं, जिन की खपत सौ टन से नीचे होती है, उन को बिल्कुल एग्जैम्पट किया गया है, उन को पूरा-पूरा दिया जाता है । जन के इखराजात सौ टन से ऊपर हैं, उन के लिये कटौती की गयी है ।

श्री बड़े : फौरेन कंट्रीज से जो न्यूजप्रिंट मंगवाने की व्यवस्था की गई है, उस के वितरण के सम्बन्ध में शासन ने क्या विचार किया है ?

श्री मनुभाई शाह : छः करोड़ रुपये का खाना फारेन एक्सचेंज इस इंडस्ट्री पर खर्च किया जाता है । आज की हालत में उस से ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते हैं । जिन की दस हजार तक का डिस्ट्रिब्यूशन है, उन को ८.५७ पेजिज प्रति दिन के हिसाब से दिया जाता है ।

Shri D. C. Sharma: How much of this newsprint is imported from Sweden and how much from other countries? Also, how is the foreign exchange requirement to have this import, met?

Shri Manubhai Shah: It is all free foreign exchange except some quantity which comes from the rupee-payment countries. The country-wise break-up varies because it depends on the international price. A large bulk of it comes from Sweden.

श्री रा० शि० पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात में कितने वर्ष लगेंगे, जब कि फोरेन इम्पोर्ट बिल्कुल बन्द हो जायेगा और हम लोग अपने देश की आवश्यकता को लोकली पूरा कर सकेंगे ?

श्री मनुभाई शाह : इस देश में रीडरशिप इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिन तीन और प्लान्ट्स के लगाने का विचार है, उन के लग जाने के बाद भी न्यूजप्रिन्ट की कंजंम्पशन बढ़ती रहेगी ।

Shri Koya: From the statement, it is found that additional quota is not given for increased circulation. May I know whether any additional quota is given for increase in pages of supplements?

Shri Manubhai Shah: No, Sir.

श्री तुलसीदास जाधव : अपने देशमें न्यूज़प्रिन्ट की जो कमी है, उस को पूरा करने के लिये क्या सरकार और कारखाने खोलने का विचार कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : तीन और कारखाने खोलने के बारे में सोचा जा रहा है ।

डा० गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात याद है कि मध्य प्रदेश में नेपा में जो अखबारी कागज़ का कारखाना है, उस को बढ़ाने के लिये वह कई बार आश्वासन दे चुके हैं और मध्य प्रदेश में और भी कई ऐसी जगहें हैं, जहां पर अखबारी कागज़ बन सकता है । क्या नेपा के कारखाने को बढ़ाने के लिए और नए कारखाने स्थापित करने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : नेपा की कैपिसिटी डबल की जा रही है । बाकी मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है । नेपा में भी जो तकलीफ है, वह रा मैटीरियल की है । और ज्यादा कारखाने वहां लगाने की गुंजाइश नहीं है । जहां-जहां शूगर फ़ैक्ट्रीज़ हैं, वहां पर उनके बगास से न्यूजप्रिन्ट बनाने का प्रबन्ध किया जा सकता है ।

Shri H. P. Chatterjee: For manufacturing paper, pulp is necessary, and for that the requisite amount of afforestation is very necessary. In connection with the NEPA mills, Government have been asking State Governments to do afforestation. How much have we progressed towards that?

Shri Manubhai Shah: Afforestation comes under Vana Mahotsava.

Shri H. P. Chatterjee: I had put a similar question before. He could not answer then. Now he has had sufficient time to collect the information.

Mr. Speaker: If the question was such that it could not be answered, what could I do?

Shri H. P. Chatterjee: The Centre has given money to the States for afforestation. I want to know how much afforestation has been done by them.

Mr. Speaker: He may table a separate question and the answer will be given.

Shri Heda: May I know whether Government propose to put any curb on the production of Indian plants which have undertaken manufacture of newsprint or semi-newsprint?

Shri Manubhai Shah: No curb has been placed.

Shri Heda: Curb on distribution?

Shri Manubhai Shah: The entire distribution is controlled.

श्री भक्त दर्शन: : अखबारी कागज में जो ढाई प्रतिशत की कटौती की गई हैं, देर से देर कब तक उस की पूर्ति कर दिये जाने की आशा की जाती है ?

श्री मनुभाई शाह : निकट भविष्य में उस को विदड्रा करने का कोई ख्याल नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि बहुत से ऐसे अखबार हैं, जिन को कागज दिया जाता है और जो उस कागज को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं ? क्या उन पर किसी प्रकार की रोक लगाई गई है ?

श्री मनुभाई शाह : वह किशायत सही है, लेकिन हम ने इस बारे में बहुत कोशिश की है। अब आडिटर के सर्टिफिकेट बहुत कड़े कर दिये गए हैं और बारबार इन्स्पैक्शन किया जाता है। इसीलिये पिछले साल ऐसे बहुत कम केसिज हमारे नोटिस में आये हैं, जहां अखबारी कागज का ग़लत इस्तेमाल किया जाता हो ।

Production of Antibiotics

*87. **Shri Surendra Pal Singh:** Will the Minister of **Commerce and Industry** be pleased to state:

(a) whether in view of the present national emergency, any efforts are being made to increase the production of antibiotics in the public sector; and

(b) if so, what special efforts are being made in this connection and whether any fresh and revised targets have been set for future production?

The Minister of Industry in the Ministry of Commerce and Industry (Shri Kanungo): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

In view of the emergency all efforts are being made to increase the production of antibiotics in the Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri. The production of penicillin which has already been stepped up from 43 mmu in 1960-61 to 45 mmu in 1961-62 has been further increased and is expected to reach 50 mmu during 1962-63. With the addition of two more fermentors, the production of penicillin will be increased to 60 mmu during 1963-64.

A Streptomycin plant with a capacity of 45 tonnes per annum has been installed and trial production has been commenced. The expansion of its capacity to 90 tonnes per annum will be completed by the end of 1963. Schemes for the production of other antibiotics like Tetracyclines are being taken on hand.

A capacity of 140 mmu per annum of penicillin along with 215 tonnes per annum of other antibiotics is being established at Rishikesh under the Indian Drugs and Pharmaceuticals with Soviet collaboration. Efforts are being made to achieve the proposed capacity in the Third Plan period.

Shri Surendra Pal Singh: What is the country's total annual requirement of antibiotics, and what percentage of that requirement is met by indigenous production?

Shri Kanungo: The total demand is estimated at 90 million mega units, out of which the present installed production is about 65 million mega units. Extension are there, and, as mentioned in the statement, when the Rishikesh plant goes into production, there will be a surplus over the demand.

Shri Surendra Pal Singh: What is the total quantity of antibiotic drugs received by India from foreign countries as free gift during 1961-62?

Shri Kanungo: I have not got that figure.

श्री म० ला० द्विवेदी : जो स्टेटमेन्ट सभा-पटल पर रखा गया है, उस में लिखा है "दि प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टिड टु रीच फिफ्टी एम एम यू डयूरिंग १९६२-६३" । चूंकि १९६२-६३ बीत चुका है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि प्रोडक्शन की कैपिसिटी १९६३-६४ में ५० एम एम यु तक पहुंचेगी, या वह १९६३-६४ में वहां तक पहुंच चुकी है । इस समय क्या स्थिति है ?

श्री कानूनगो : हमारी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी ५० मैगायूनिट्स है और करीब करीब उतनी ही प्रोडक्शन हो रही है ।